चीनी उद्योग की बदहाली दूर करने के लिए नीति बदलेगी केंद्र सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। चीनी उद्योग को संकट से उबारने की कसरत में जुटी मोदी सरकार ने इससे जुड़ी नीति में बदलाव लाने का फैसला किया है। एक उच्चस्तरीय बैठक में चीनी उद्योग के खस्ता हालत पर विचार के बाद सरकार इस बात पर सहमत है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए नीति बदलनी पड़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल चीनी उद्योग को राहत पैकेज देने या गन्ने का मूल्य बढ़ाने के बजाय समस्या के स्थायी समाधान के पक्ष में हैं। पीएम ने मंत्रियों से किसान हित को सर्वोपरि रखते हुए नई नीति बनाने पर जोर दिया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए सरकार नए सिरे से चीनी नीति लाने पर विचार कर रही है। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए किए गए प्रयास की जानकारी लेते हुए पीएम ने उपभोक्ता एवं नागरिक आपूर्ति और पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रजेंटेशन को भी देखा। पीएम मोदी ने निर्यात की संभावनाएं तलाशने के साथ ईंधन में एथनॉल की मात्रा बढ़ाने पर जोर दिया। पीएमओ के अनुसार मोदी ने गन्ना किसानों को संकट से उबारने के लिए चीनी उद्योग को दिए गए 6000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की भी समीक्षा की है। निचले स्तर से इस बात की शिकायत मिल रही है कि राहत पैकेज के बावजूद किसानों को राहत नहीं मिली है। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि पीएम मोदी ने किसानों के हित को सर्वोपरि रखने को कहा है। वह गन्ना किसानों की समस्या का स्थायी हल निकालने के पक्ष में हैं। बीते दिनों खुद भाजपा सांसदों ने मामले को संसद में उठाते हुए सरकार से दखल की गुहार लगाई थी। पीएम ने मंत्रियों और नीति आयोग के अधिकारियों से भी बातचीत की है। पीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन, कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान समेत तमाम मंत्रालयों और नीति आयोग के आला अधिकारी मौजूद थे।

पीएम ने संकटग्रस्त चीनी उद्योग की स्थिति का लिया जायजा, गन्ना किसानों के बकाए पर उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा

किसानों का 8 हजार करोड़ बकाया

उत्तर प्रदेश में 95 निजी और 23 सहकारी चीनी मिलें हैं। मौजूदा समय में प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का 7 हजार 827 करोड़ रुपये का बकाया है। गन्ना उत्पादन में यूपी देश भर में अव्वल और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। यूपी गन्ना निदेशालय के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2014-15 में गन्ने का क्षेत्रफल 21.30 लाख हेक्टेयर था।

Amar Uzala.
2/8/15